सार्क शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाषण

दिनांक 12 नवम्बर 2005
ढाका

सबसे पहले मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री माननीय बेगम ख़ालिदा ज़िया को सार्क का अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक वधाई देता हूँ । इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए बांग्लादेश की सरकार और जनता ने जो इतने अच्छे इंतजाम किए हैं उसके लिए भी मैं उनकी दिल से सराहना करता हूँ । ढाका पहुँचने से लेकर अब तक जिस गर्मजोशी और दोस्ताना ढंग से हमारी आवभगत हुई है उससे हम अभिभूत हैं ।

मैं इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष पाकिस्तान की सार्क प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की अटल वचनबद्धता और उत्साह के साथ काम करने के लिए सराहना करता हूँ ।

इस वर्ष हमारे क्षेत्र को बड़ी-बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है । वर्ष के आरंभ में श्री लंका, मालदीव और भारत सुनामी से प्रभावित हुए थे और अब पाकिस्तान और भारत को बड़े भूकंप से क्षति हुई है जिसने पूरे के पूरे शहरों और गांवों को तबाह कर दिया है । हमें अपने नागरिकों और दक्षिण एशिया के उन लोगों के लिए दुःख है जिन्हें इस विपत्ति में अपनी जान गंवानी पड़ी है और हम प्रभावित लोगों की सहायता करते रहेंगे और उनके जीवन को संभालने की कोशिश करते हुए इस समस्या का समाधान करेंगे ।

इन विपत्तियों ने इस बार फिर हमें इस बात की याद दिला दी है कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए सामूहिक संसाधनों को इक्ट्ठा करने के लिए दूसरे देशों के साथ गठबंधन की आवश्यकता है। इस शिखर सम्मेलन से विपत्ति के समय राहत प्रबंधन के लिए कारगर और समय पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय तंत्र तैयार किया जाए । हमने भाईचारे की भावना से अपने पड़ोसियों की विनम्र सहायता की है और हम इससे अधिक सहायता करने के लिए भी तैयार हैं । हमें इस बात की खुशी है कि आपदा प्रबंधन के लिए सार्क केन्द्र का मेज़बान बनने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है ।

आपदा प्रबंधन ऐसा मामला है । जिसकी जरूरत ने हमें गंभीरता के साथ इस पर सोचने के लिए बाध्य कर दिया है । इस मामले में चेतावनी प्रणाली से लेकर राहत और पुनर्निर्माण तक सार्थक सहयोग की संभावनाएं हैं । दक्षिण एशिया के ताजे अनुभव को देखते हुए इस क्षेत्र में हमें और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश ने योजना बनाने और जोखिम प्रबंधन में समुदाय (जनता) को शामिल करते हुए आपदा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नई सोच विकसित की है । पूर्व - आपदा जोखिम में कमी के लिए और आपदा के बाद पुनर्निर्माण और पुनर्वास दोनों के लिए माइक्रो क्रेडिट का प्रयोग पूरे विश्व में बेहतरीन परिपाटी के रूप में जाना जाता है । जिसे दक्षिण एशिया के अन्य देशो में दोहराना फायदेमंद है ।

अध्यक्ष महोदया,

सार्क अपने 20 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है । यही वह शहर है जहां से सभी की सृमद्धि के सामूहिक लक्ष्य के लिए हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी । राष्ट्रपति जिया-उर्र-रहमान के विचारों ने सार्क की अवधारणा को आगे बढ़ाने में सहायता दी थी और पहले सार्क अवार्ड के साथ इस शिखर सम्मेलन में हम उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं ।

सार्क यात्रा के इस पड़ाव पर यह सवाल करना उचित है कि इन 20 वर्षों में क्या हमने क्षेत्रीय सहयोग के लिए बनाई गई आरंभिक रूपरेखा के साथ न्याय किया है । इसका सही उत्तर यह है कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग हमारी आशाओं की तुलना में कम रहा है। यह एशिया और विश्व के अन्य क्षेत्रों दोनों में अधिक सफल मामलों से बहुत पीछे रहा है। मैं आशा करता हूँ कि पहली जनवरी, 2006 से 'साफ्टा' (एस ए एफ टी ए)प्रभाव में आया है लेकिन इसके बावजूद यह केवल क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के हमारे लक्ष्य के अर्थ में हमारी छोटी सी शुरूआत का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

यह महत्वपूर्ण है कि हम विस्तृत एशियाई संदर्भ में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग का मूल्यांकन करते हैं । आज आसियान वास्तविक एकीकृत आर्थिक समुदाय तेजी से विकसित हो रहा है । इसी के समानांतर प्रस्तावित पूर्वी एशियाई आर्थिक शिखर सम्मेलन के संदर्भ में आर्थिक एकीकरण के लिए अंतरा-आसियान (एचएऐ)एकीकरण व्यापक आंदोलन है । हम यह साफ-साफ देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद से पहले के व्यापार और वाणिज्य के मुख्य मार्गों के पुनर्निर्माण के आधार पर एशिया का पुनरूत्थान किसी भी प्रकार से कम नहीं है और उसने एशिया की विशिष्ट पहचान बनाई है और उसे पहले स्थान पर ला खड़ा किया है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सार्क एशिया के पुनरूत्थान का अभिन्न हिस्सा बनने के लिए तैयार है या वह अपने दायरे में अलग-अलग पड़े रहने से ही खुश है ? यदि हमारा क्षेत्र विकासोन्मुख एशिया का हिस्सा बनना चाहता है तो जो विकास हमारे पड़ोसी देशो में हो रहा है उसी के मद्दे नजर हमें भी काम करना चाहिए बल्कि तेजी से काम करना चाहिए ।

एशिया में हम ऐसे मिलन स्थ्ल पर हैं जहां हमारे उप- महाद्वीप को अद्वितीय सभ्यता की विशेषताएं हासिल हैं हमारी संस्कृति की मिली जुली परम्पराएं ,अपने लोगों की मिलनसारिता और असीम सृजनात्मकता जो एक विचार में से दूसरे विचारों के निकलते रहने से उत्पन्न होती है ।

यदि एक क्षेत्र के रूप में सार्क संस्कृति और वाणिज्य के मिलन स्थल के रूप में अपनी भूमिका को पुनः प्राप्त कर लेता है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर माल, लोगों और विचारों की निर्बाध आवाजाही में आने वाली बाधाएं हटा दें । हम अब तक एशिया का मिलन स्थल नहीं बन सके हैं बल्कि अभी भी अपने क्षेत्र के अंदर कटे हुए हैं । अपने क्षेत्र से जुड़े बिना एशिया में जुड़े रहना संभव नहीं है या इस जुड़ाव की संभावना बहुत कम है । प्राचीन आड़े तिरछे मार्ग उप-महाद्वीप को आपस में जोड़ते हैं और समुद्री पत्तनों को जोड़ते हैं जिनसे शेष विश्व में प्रवेश किया जा सकता है । हमारी नदियां जलमार्ग बनाती हैं जिनसे लोग और सामान एक क्षेत्र से दूसरे

क्षेत्रों में पहुँचते हैं उप-महाद्वीप के अंदर यह जो प्राचीन संपर्क क्षमता है वह उपनिवेश युग में आधुनिक रेल मार्गों और पक्के राजमार्गों से बहुत अधिक हो गई थी । हमारे तटों पर बने पुराने समुद्री पत्तन शिपिंग के नए ताने- बाने उपनिवेशी वाणिज्य के नए चैनलों का हिस्सा बन गए थे । उपनिवेशवाद ने हमारे क्षेत्र में खूब संपदा पैदा की लेकिन वह संपदा हमारे लोगों के लिए नहीं थी बल्कि एक तरह से यह साम्राज्यवाद के लिए लूटपाट थी ।

यदि हम चाहते हैं कि अगले बीस वर्ष सार्क देशों के लिए बिल्कुल अलग प्रकार के हों तो हमें एक ओर तो उपमहाद्वीप के देशों को फिर से जोड़ने का सबसे पहले निर्णय, लेना होगा और दूसरी ओर उसके बाद बड़े एशियाई पड़ोसी देशों के उपमहाद्वीप को फिर से जोड़ना होगा । हमें यातायात और संप्रेषण के तरीकों को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाने और उन्हें फिर से तैयार करने की आवश्यकता है जो हमें आपस में जोड़ सकें और उसके बाद हमारे क्षेत्र को शेष एशिया से जोड़ सके ताकि हमारे क्षेत्र में समृद्धि आ सके और जिस पर निस्सन्देह हमारा हक है । इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए इस शिखर सम्मेलन में हम सबको इस बात से सहमत होना चाहिए कि सभी दक्षिण एशियाई देश परस्पर एक दूसरे को तीसरे देश में जाने की सुविधा प्रदान करेंगे जो सिर्फ एक दूसरे देश को ही नहीं जोड़ेंगे बल्कि बड़े एशियाई पड़ोसी देशों को खाड़ी में मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को भी जोड़ेंगे । भारत जिसकी सीमा दक्षिण एशिया के सदस्यों की सीमा से लगती है ऐसा ही करने का इच्छुक है ।

इस अवसर पर मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि भारत दक्षिण एशियाई कार रैली आयोजित करना चाहता है । यह हमारे अगले शिखर सम्मेलन का आधार होगा । इससे स्पष्ट रूप से हमारी एक क्षेत्रीय पहचान बनेगी और हमारी सार्क यातायात संरचना को सुधारने की आवश्यकता पर ध्यान दिलाएगा ।

हमे एक देश से दूसरे देश को जोड़ने की हवाई व्यवस्था में भी सुधार लाना चाहिए । भारत अपने सभी सार्क पड़ोसी देशों को पारस्परिक आधार पर और मौजूदा नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हमारे दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, बेंगलूर, हैदराबाद और कोलकाता महानगरों के लिए निर्धारित (सरकारी) एयरलाइनों से रोजाना इसके अलावा जितनी वे चाहें उतनी हवाई सेवाएं देने के साथ -साथ पूरे भारत में 18 अन्य स्थानों तक हवाई सुविधाएं देने को तैयार है । मैं सार्क देशों की सरकारी एयरलाइनों को पारस्परिक आधार पर सार्क क्षेत्रों के बीच और उससे आगे दोनों के लिए पांचवे स्वतंत्रता अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा भी देना चाहता हूँ । हमें अधिक हवाई सेवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और इसके लिए हमारे हवाई करार में एयरलाइनों के अधिक गंतव्य उपलब्ध कराना लाभदायक हो सकता है ।

अपनी सीमाओं के बाहर लोगों और माल की उदार आवाजाही के लिए सभी सदस्य देशों को अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। ताकि संबधित पक्षों को प्रेरित किया जा सके । किसी भी सदस्य देश को किसी अन्य सदस्य देश के हितों के विरूद्ध अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । सीमा पार से आतंकवाद और विद्रोही ग्रुपों और आपराधिक तत्वों को आश्रय देने को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए । ऐसा आपसी विश्वास के वातावरण में ही हो

सकता है और तभी हो सकता है जब हम आतंकवाद के उत्पीड़न के खिलाफ सामूहिक रूप से वचनबंध हों ताकि हम अधिक पारस्परिक बातचीत से अपेक्षित प्रगति दर्ज कर सके ।

अध्यक्ष महोदया,

हमारे उपमहाद्वीप के लोग विश्व के अत्यधिक आधुनिक स्तर के वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान कर रहे हैं और विश्व के विद्धानों की अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं जहां कहीं हमारे प्रतिभाशाली लोगों को अनुकूल वातावरण और विश्व स्तरीय सुविधांए मिलती हैं वे पलायन कर जाते हैं । मैं आप सब लोगों के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि क्यों न हम सात सदस्य देश अपने संसाधनों को एकत्र करके दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के रूप में विशिष्ट केंद्र तैयार करें जो हमारे क्षेत्र के प्रत्येक देश से आने वाले विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं को विश्व स्तर की सुविधाएं और प्रोफेशनल विद्वान उपलब्ध करा सकें । आइए इसे हम एक ऐसा मंच बनाएं जहां से हमारे शिक्षाविद्, विद्वान, अनुसंधानकर्ता और प्रतिभाशाली विद्यार्थी वर्ग तरक्की के लिए मिलकर काम कर सके । भारत अगले तीन से चार वर्षों में इस प्रोजेक्ट को वास्तविक रूप देने में अधिक योगदान देने का इच्छुक है। हम निश्चित रूप से इस संस्थान की मेज़बानी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही यदि कोई अन्य सदस्य देश ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो हम उसे सहयोग देने के लिए भी तैयार हैं ।

मैं आपके सामने एक ऐसा सहयोग पर आधारित प्रोजेक्ट रखना चाहता हूँ जिस पर विचार किया जा सकता है । हमारे सभी देशों के लिए खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि हमें एक क्षेत्रीय खाद्यान्न बैंक स्थापित करना चाहिए । जिसमें सभी सदस्य देश योगदान देंगे और इसका प्रयोग हमारे किसी भी सदस्य देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली कमी और हानियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा । इससे पूरे क्षेत्र में भंडारण डिपो का नेटवर्क बन सकेगा जिसमें उनकी क्षमता और अधिशेष की उपलब्धता के आधार पर सदस्य देश अपने हिस्से का योगदान देंगे ।

इसी प्रकार हमारे क्षेत्र द्वारा जिस बड़ी चुनौती का सामना किया जा रहा है वह है ऊर्जा सुरक्षा, विशेषतौर पर जब हमारी अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार हो रहा है इसलिए हम भविष्य की नीति तैयार करने में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर सकते हैं । मैं विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों, कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों को दक्षिण एशियाई ऊर्जा विचार विमर्श में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूॅ ताकि वे ऐसी संभावनाओं का पता लगाने के उपायों का सुझाव दे सकें ।

मैं यहां कुछ अन्य सिफारिशों का उल्लेख करना चाहूँगा जिन्हें भारत, आप सब लोगों के सामने रखना चाहता है । एक वर्ष पहले भारत ने करार द्वारा गरीबी उन्मूलन निधि बनाने के लिए 100 मिलियन डालर देने की पेशकश की थी जिसके संबंध मे कहा गया था कि इस राशि का प्रयोग भारत को छोड़कर सार्क के अन्य देशों में परियोजनाओं पर किया जाएगा लेकिन हमें खेद है कि पिछले वर्ष में हमें किसी भी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ । हम विभिन्न मौजूदा और

प्रस्तावित निधियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न 'विंडो' के साथ 'अम्ब्रेला साउथ एशियन डेवलपमेन्ट फंड' में मिला देने के निर्णय का स्वागत करते हैं ।

हमने एच आई वी / एड्स और टी बी के संबंध में लोगों को और अधिक जागरूक करने संबंधी प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए भी कदम उठाए हैं और इन बीमारियों से निपटने के लिए इस क्षेत्र में चिकित्सा कुशलता और क्षमता को बढाने का प्रयास कर रहे हैं । फिर भी हम इस दिशा में बहुत अधिक प्रगति नहीं कर पाए हैं मैं सहयोग पर आधारित एक स्वास्थ्य रक्षा प्रोजेक्ट स्थापित करने का सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें एक क्षेत्रीय टेलीमेडीसन नेटवर्क होगा । हमें सभी सार्क देशों को जोड़ने वाली एक सुविधा स्थापित करके इस क्षेत्र में अपनी सुविज्ञता देने में प्रसन्नता होगी ।

इससे पहले कि वर्ष 2020 तक दक्षिण एशिया आर्थिक संघ बनाए जाने की योजना तैयार करने वाले हमारे सहयोगी देशों के जाने माने व्यक्तियों का एक समूह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे । मैं उन मूलभूत निर्णयों का हवाला देना चाहूँगा जिनकी आवश्यकता हमें इस लक्ष्य को पाने के लिए पड़ेगी जुलाई की सचिवीय बैठक में हमने सार्क हाई इकोनोमिक काउंसिल की स्थापना की सिफारिश की थी जो स्पष्ट रूप से ऐसे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की ओर आगे बढ़ने के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था, व्यापार, वित्त और मौद्रिक क्षेत्रों में होने वाले कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ही थी ।

दक्षिण एशिया में उत्तम हस्तशिल्प और वस्त्रों की समृद्ध और जीवन्त परम्परा है । प्रत्येक सदस्य देश की अपनी अद्वितीय संस्कृति है और उनकी विशिष्ट शिल्प परम्परा है । भारत को 'सार्क वस्त्र और हस्तशिल्प संग्रहालय' स्थापित करके इस बहुमूल्य विरासत को सुरक्षित रखने और उसको बढाने में खुशी होगी । इस संग्रहालय से शिल्पियों को प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा डिज़ाइन कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकेगा और यह संग्रहालय दस्तकारों द्वारा फैशन शो और प्रदर्शनी जैसे आयोजन करेगा और अनुसंधान कार्य भी करेगा । इससे हम वस्त्रों और हस्तशिल्प के क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपनी प्रत्येक राजधानी में रिटेल आउटलेट स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदया,

अब मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी एसोसिएशन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत की अटल वचनबद्धता का आश्वासन देता हूँ । सार्क के रूप में हमें वर्तमान परिवर्तनों का निश्चित तौर पर हिस्सा बनना चाहिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में और एक क्षेत्र के रूप में हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उनका समाधान सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खोजा जा सकता है । इस सोच की बहुत जरूरत है कि हम पारस्परिक लाभदायक आर्थिक साझेदारी के नव निर्माण के लिए इतिहास और राजनीति के दायरे से बाहर आकर बदलाव लाएं । भारत इसक ा हिस्सा होने के नाते इन प्रयासों के लिए सदैव तैयार रहेगा ।

धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया ।